ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेज:4 औषधीय गुणों से भरा पूरा होता है बांसकरील

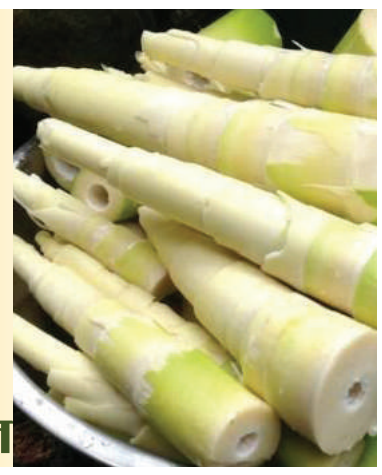

रविवारीय, 26 जुलाई - 01 अगस्त 2020 वर्ष- एक, अंक-51, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्य:5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी, पेंट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं व्हाट्सएप नंबर है।
greenrevolt2019@gmail.com
9798166006

पुलिस पिकेट बनने से बर्बाद हो रही है उग्रतारा मंदिर स्थित नदी

संवाददाता

- नदी में मिट्टी भरकर यहां पुलिस पिकेट का निर्माण किया गया है।
- पिकेट दो पहाड़ों के तल पर है, जो सुरक्षा के मापदंड के भी विपरीत है
- मंदिर से आधा किमी की दूरी पर पहले से ही एक पिकेट है।

रांची-चतरा मार्ग में चंदवा से 8 किमी की दूरी पर नगर ग्राम अवस्थित है। इस ग्राम में प्रसिद्ध उग्रतारा मंदिर है, जहां देश के अनेक स्थानों से दर्शनार्थी आते हैं। इस मंदिर के उत्तर दिशा में एक नदी है। इस नदी के जल का प्रयोग मंदिर में शारदीय नवरात्र के समय पूजा में किया जाता है। दूसरी ओर यह नदी मंदिर के ठीक बगल से होकर गुजरती है, इसलिए मंदिर की रमणिकता और भी बढ़ जाती है, किंतु विगत दो वर्षों से प्रशासनिक स्तर से जो परिवर्तन किया गया, इससे यह नदी कराह रही है।

2018 ई में तत्कालीन डीजीपी डीके पांडेय द्वारा नदी में मिट्टी भरकर यहां पुलिस पिकेट का निर्माण कराया गया है। इस पिकेट के निर्माण में कानून की धज्जियां भी उड़ायी गयी है। यथा यह जमीन गैरमजरूआ तथा नदी में स्थित है और दो पहाड़ों के तल पर है, जो सुरक्षा के मापदंड के भी विपरीत है। जबकि मंदिर से आधा किमी की दूरी पर एक पिकेट है। अगर आवश्यकता थी तो बने हुए पिकेट को ही अपग्रेड किया जा सकता था। यहां एनजीटी और सुरक्षा दोनों मानदंड को दरकिनार करते हुए पिकेट को बनाया गया और साथ ही टेंडर में भी गड़बड़ी की गयी। इस जमीन को बंदोबस्त करा लिया गया, इस कृत्य से अंचल कार्यालय भी जांच के घेरे में आ जाता है। इस कृत्य में तत्कालीन सरकार भी खामोश रही, जबकि अखबार में बराबर इस विषय को ध्यानाकृष्ट कराया जाता रहा, फिर इसकी अनदेखी होती रही।

नदी को बचाने के लिये यहां से पुलिस पिकेट हटाया जाये और नदी को उसके मूल रूप में बहने दिया जाये।

नदी को बर्बाद कर कर बना है पुलिस पिकेट

दुनिया के लिए आसान नहीं है प्लास्टिक कचरे को कम करने की डगर

दुनियाभर में प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं पर इसके बावजूद इस कचरे में लगातार वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार यदि देश प्लास्टिक से बने उत्पादों की बिक्री और उपयोग को सीमित करने में सफल रहते हैं, इसका कोई विकल्प ढूंढ लेते हैं, इसे समुद्रों में पहुंचने से रोक लेते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट में आधे से कम की कटौती की जा सकती है। हालांकि दुनियाभर के देशों और कंपनियों ने प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के अनेक उपाय और घोषणाएं की हैं, लेकिन इस-के बावजूद इन सब उपायों से प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा में केवल 7 फीसदी की कटौती हो सकती है।

शोध के अनुसार यदि आज उपलब्ध तकनीकों का बेहतर ढंग से उपयोग किया जाए तो समुद्रों में बढ़ रहे प्लास्टिक वेस्ट में 80 फीसदी से भी ज्यादा की कटौती की जा सकती है। इसके लिए नीति निर्माताओं को बड़े परिवर्तन करने की जरूरत है।

राज्य में कोरोना मरीजों की एकाएक बढती संख्या, बाजारों में भीड़ और सरकार की लापरवाही से तो यही लग रहा है कि

आत्मघाती बन रहा है झारखंड

मनोज कुमार शर्मा

रांची : जब राज्य में कोविड -19 मरीजों की संख्या कम थी, कम्युनिटी ट्रांसफर जैसा कोई खतरा नहीं था और राज्य में उंगलियों पर गिनने लायक मरीज थे तब झारखंड में लोग ज्यादा सतर्क और चाक चौबंद थे। हरेक चेहरे पर मास्क हाथों में ग्लब्स और जेब में सैनिटाजर था। लेकिन आज जब स्थिति भयावह होती जा रही है तब लोग ज्यादा लापरवाह हैं। लॉकडाउन में ढिलाई की वजह से लोगों में लापरवाही घर कर गयी है। शुरूआती भय से उपजी सतर्कता अब गायब है। झारखंड में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है इसका मुख्य कारण सख्त लॉकडाउन के बाद मिली छूट में लोग उच्छृंखल लापरवाह होते गये और सरकार ने भी सख्ती के बजाय लोगों को सिर्फ डराने के मकसद से बिना मास्क वालों चलने वालों को एक लाख रूपये जुर्माने और दो साल जेल भेजने जैसी बेसिर पैर की बातें कहीं।

इधर आइएमए का कहना है कि झारखंड अब कम्युनिटी ट्रांसफर के दौर में प्रवेश कर गया है। अगर इस बात में सच्चाई है तो राज्य के लिये यह बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि झारखंड में दिल्ली मुंबई की तरह हजारो बेड और चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं और उपलब्धता के बाद भी दिल्ली मुंबई में मरीजों का क्या हश्र हुआ हम सब ये भी देख चुके हैं।

झारखंड में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होते ही स्थिति चरमराने लगी है। अगर संक्रमण की रफ्तार देश के अन्य राज्यों जैसी हुई तो यहां हालात बिगड़ सकते हैं। अब झारखंड में प्रतिदिन दो सौ से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स में चिकित्सकों और बेड की कमी के कारण मरीजों को कोई देखने वाला नहीं मिल रहा है। चिकित्सक और नर्स खुद संक्रमित हैं। कई जानकारों का तो कहना है कि जांच की रफ्तार बढ़ायी जाये तो संक्रमितों की बाढ़ आ जायेगी? क्योंकि झारखंड में अब तक सिर्फ ढाई लाख सैंपल ही जांचे गये हैं। इसी सरकारी अव्यवस्था पर हाइकोर्ट ने जांच और इलाज में तेजी लाने को कहा है।

प्रतीकात्मक चित्र

सिर्फ जुलाई में 5500 मरीज सख्ती की उम्मीद नहीं

सिर्फ 25 जुलाई तक ही झारखंड में साढे पांच हजार संक्रमित मिले हैं। अब रोज दो ढाई सौ मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि सरकार फिर सख्ती से लॉकडाउन लागु करेगी, पर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अगर अभी लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिये पहले जैसा सख्ती से लागु कर दिया जाये तो संभव है राज्य बड़े खतरे और कम्युनिटी ट्रांसफर से बच जाये।

देश के अन्य राज्यों में जब कोरोना कहर ढा रहा था उस वक्त झारखंड में हालात काबू में दिख रहे थे। तब मुख्यमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि झारखंडी बहुत मजबूत होते हैं।राज्य में हालात मुंबई, दिल्ली की तरह भयावह नहीं है, पर उसके बारे में सोंच कर लोगों का भयग्रस्त होना लाजमी है।

आम लोग बेपरवाह हैं

रांची में चैंबर आफ कॉमर्स के सप्ताह में तीन दिन दूकान बंद रखने के निर्णय के बाद भी सातो दिन बाजार खुले हुये हैं। लोग बाहर निकलते हैं और सिर्फ मास्क पहन कर बचाव की खानापुर्ति कर ले रहे हैं,सड़क किनारे समूह में समोसे और लिट्टी खा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि प्रबुद्ध और जिम्मेदार लोग जैसे पूर्व नगर विकास मंत्री,सरकार के मंत्री, कई पत्रकार, रांची विश्वविद्यालय के पदाधिकारी से लेकर पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं। कुछ की दलील है कि काम नहीं करेंगे तो खायेंगे कहां से! इसी चक्कर में लोगों ने खुद को भगवान भरोसे छोड़ दिया है।

झारखंड में स्थिति भयावह हो सकती है

झारखंड में कोरोना का संक्रमण देर से हुआ था। और देश भर में प्रकोप के बाद भी लंबे समय तक यहां कोई मरीज नहीं मिला था। मार्च से जून तक ढाई हजार से भी कम केस थे लेकिन आ सिर्फ जुलाई में ही राज्य में यह आंकड़ा छह हजार के करीब है साठ से ज्यादा मौते कोरोना से हो चुकी है। ऐसा सिर्फ झारखंड में नहीं है बल्कि पूरे देश में अब प्रतिदिन 40 से 50 हजार मरीज मिल रहे हैं।

झारखंड में अगर अन्य राज्यों की तरह मरीजों की बाढ आयी तो यहां हालात संभाले नहीं संभलेंगे। यहां अस्पताल से लेकर चिकित्सकों और बेड तक की कमी है। जांच की रफ्तार धीमी है। मरीजों की संख्या में बढोतरी होते ही रिम्स की स्थिति चरमरा गयी है। आनन फानन में रिम्स और खेलगांव में बेडों की संख्या बढायी जा रही है, रांची के सदर अस्पताल में घंटों खड़े रहने के बाद भी जांच नहीं हो पा रही है लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये हालात तब हैं जब मरीजों की संख्या में अभी मामूली बढोतरी हुयी है। अगर आइएमए के कहे अनुसार यहां कम्युनिटी ट्रांसफर होती है तो यह सारे इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरा साबित होंगे। सड़कों पर मरीज इधर उधर लेटे मिलेंगे। रांची विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने भी संक्रमित होन पर चिकित्सकों से मदद की गुहार लगायी तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं मिल रहा था। वहीं रांची नगर निगम के सफाईकर्मियों के पास बचाव के कपड़े ग्लब्स तक की कमी है।

ध्यान देने लायक बात ये है कि जनप्रतिनिधि और जिन पर संक्रमण रोकने का दारोमदार है वही लोग खुद लापरवाह होकर संक्रमित हो रहे हैं और सरकार भी किस्मत के भरोसे जूझ रही है।

कम लागत में सालोभर आमदनी का जरिया : बेबीकॉर्न की खेती

रांची : बेबी कॉर्न मक्का फसल की एक प्रजाति होती है. बेबी कॉर्न की खेती साल में 2 से 3 बार सुगमता से की जा सकती है. कम लागत में अच्छी आमदनी के लिए बेबी कॉर्न की खेती प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है. एक हेक्टेयर भूमि में बेबी कॉर्न की खेती के द्वारा 1 से 2 लाख रुपए की आय आसानी से प्राप्त की जा सकती है. जबकि, इसकी खेती 25 से 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत आती है. यह मक्का का प्री-मैच्योर भुट्टा होता है, इसलिए इसे शिशु मक्का कहा जाता है. सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदेश में इसका उत्पादन मुख्यत: खरीफ के मौसम में किया जाता है. एक हेक्टेयर कृषि भूमि में बेबी कॉर्न पैदा करने के लिए लगभग 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है. इसके प्रमाणित बीज 200 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलते हैं. इसके अलावा बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशक व अन्य लागत पर 6 से 10 हजार रुपए का खर्च आ जाता है. इसमें जल्दी पैदावार देने वाली (55 से 60 दिनों में) एचएम -4, बिरसा विकास मक्का -2 आदि उन्नत किस्मों को चुना जा सकता है. इन किस्मों में बेबी कॉर्न के सभी गुण मौजूद होते हैं.

एक हेक्टेयर बेबी कॉर्न की फसल से लगभग 16 से 20 क्विंटल बेबी भुट्टा (बिना छिलके) के प्राप्त होता है. इसके अलावा 200 से 300 क्विंटल हरा चारा भी प्राप्त होता है. गर्मियों के दिनों में बेबी कॉर्न और हरा चारा की बेहद अच्छी मांग रहती है. बेबी कॉर्न को तोड़ने के बाद नरमंजरी, रेशा एवं छिलका आदि पोष्टिक चीजें भी मिलती हैं. ये भी बाजार में आसानी से बिक जाती हैं. इसकी खुदरा कीमत 70 से 120 रुपए प्रति किलो के आसपास होती है. थोक में इसका रेट 4 हजार से 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल (क्वालिटी के अनुसार) होता है. यदि न्यूनतम दर 4 हजार रुपए प्रति क्विंटल को आधार माना जाय तो सिर्फ बेबी कॉर्न से ही 80 हजार रुपए आमदनी ली जा सकती है. इसका हरा चारा भी स्थानीय बाजा-रों में लगभग 2 से 3 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकता है. इससे करीब 60 हजार रुपए की आमदनी होती है. इस तरह यदि साल में दो बार भी बेबी कॉर्न फसल की खेती की जाय तो, इससे 3.0 लाख रुपए तक आसानी से कमाए जा सकते हैं. कतार से कतार की अधिक दूरी के कारण बेबी कॉर्न के साथ अन्य मौसमी फसलों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है. किसान इसकी बिक्री बड़े शहरों की मंडियों, होटल, रेस्तरां, कम्पनियों (रिलायन्स, बिग बाजार, सफल आदि) में कर सकते है. विदेशों में बेबी कॉर्न के आचार एवं कैन्डी की बहुत ही ज्यादा माँग है. हरियाणा के पचरंगा कम्पनी द्वारा विदेशों में बेबी कॉर्न के आचार का निर्यात किया जा रहा है. अच्छे दाम के लिए बेबी कॉर्न (छिलका उतरा हुआ) को बेचने के लिये छोटे-छोटे पोलिथीन बैग में पैकिंग किया जा सकता है. लेकिन अधिक समय तक संरक्षित रखने के लिये काँच (शीशा) की पैकिंग सबसे अच्छी होती है. काँच के पैकिंग में 52 प्रतिशत बेबी कॉर्न और 48 प्रतिशत नमक का घोल होता है. इस तरह बेबी कॉर्न को डिब्बा में बंद क-रके दूर के बाजार या अन्तराष्ट्रीय बाज़ारों में बेचा जा सकता है.

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित आईसीएआर - अखिल भारतीय समन्वित मक्का शोध परियोजना में बेबीकॉर्न की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसकी जनजातीय उपपरियोजना (टीएसपी) के तहत 2011-12 से अबतक रांची, पलामु, खूँटी एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के 30 से अधिक गाँवों के 450 आदिवासी किसानों के करीब 400 एकड़ खेतों में बेबीकॉर्न फसल का अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण कराया जा चुंका है.

परियोजना अन्वेंशक डॉ मणिगोपा चक्रवर्ती ने बताया कि टीएसपी योजना तहत कुल 400 आदिवासी किसानों को 10 प्रि-शक्षणों के माध्यम से जागरूक किया गया. किसानों के खेतों में 10 प्रक्षेत्र दिवस के माध्यम से 500 से अधिक किसानों को ...शेष पेज 3 पर

सीसीएल ने अपने कर्मियों में वितरित किये एक लाख पौधे, वृहद पौधारोपण भी करेगा

रांची : कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी के मार्गनिर्देशन में सीसीएलसहित कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियां एवं अन्य कोयला कंपनियां 23 जुलाई से 2020 को वृहद स्तर पर 'वन महोत्सव' का आयोजन किया जा रहा है। सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह के नेतृत्व में सीसीएल में 'वन महोत्सव' कार्यक्रम को लेकर पूरी सजगता से तैयारी चल रही है। सीसीएल ने 23 जुलाई को अपने सीसीएल मुख्यालय सहित सभी कमांड क्षेत्रों में अपने कर्मियों के बीच एक लाख पौधों का वितरण एवं पौधा-रोपण किया ।

सीसीएल द्वारा कथारा, बी.एण्ड के., पिपरवार, ढोरी, रजरप्पा बरका-सयाल , हज़ारीबाग, कुजू, एनके, मगध आम्रपाली, अरगड्डा क्षेत्र एवं मुख्यालय में ईको-पार्क का निर्माण किया जायेगा, जिसका शिलान्यास ''वन महोत्सव 2020'' के अंतर्गत 23 जुलाई को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गनिर्देशन में ऑनलाईन माध्यम से किया गया। चार क्षेत्रों में प्रति ईको-पार्क 20 हेक्टेयर भूमि पर जबकि दो क्षेत्रों में ईको-पार्क 10-10 हेक्टेयर भूमिपर विकसित किया जायेगा जिसमें विभिन्न जैव विविधता, मृदा संरक्षण एवं पर्यावरण संबंधीअन्य गतिविधियों को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से विस्तारित किया जायेगा। आधुनिक तकनीकी का उपयोग जैसे सीड बॉल का प्रयोग कर पौधा प्लांटेशन किया जायेगा। सीड बॉल तकनीक में बीज को मिट्टी में लपेट कर बॉल बनाते हैं और बरसात के मौसम में चयनित भूमि में फेंक कर पौधा रोपण होता है।

यह जानकारी सीसीएल केविभागाध्यक्ष जनसम्पर्क ने दी।

वन क्षेत्र में वृद्धि वाले दस देशों में भारत भी शामिल: एफएओ

एफएओ ने 2010 से 2020 के दशक में दुनिया भर के वन संसाधनों का मूल्यांकन के बाद रिपोर्ट जारी की है।संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (एफआरए) जारी किया है। इसके मुताबिक, एक दशक के दौरान वन क्षेत्र में इजाफा करने वाले दस देशों में भारत का नंबर तीसरा है।

उल्लेखनीय है कि 1990 के बाद से, एफएओ हर पांच साल में यह व्यापक मूल्यांकन जारी करता है। इस रिपोर्ट में सभी सदस्य देशों में जंगल की स्थिति और उनके प्रबंधन का आकलन किया जाता है।

जल प्रदूषण के कारण और निवारण

डॉ.कृष्ण कुमार मिश्र

आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पीएच-डी. की उपाधि प्राप्त की। आप टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई के होमी भाभा विज्ञान केन्द्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हिन्दी में लोकप्रिय विज्ञान लेखक के रूप में आपकी अपार ख्याति है । आपके 250 से अधिक लेख तथा 22 पुस्तकें प्रकाशित हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार, होमी जहाँगीर भाभा स्वर्ण पुरस्कार, शताब्दी सम्मान,राजभाषा भूषण पु-रस्कार, इस्वा सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉ.मिश्र मुंबई में निवास करते हैं।

वैज्ञानिक तौर पर पेयजल में खनिज की मात्रा कम होनी चाहिये यह सुस्वादयुक्त तथा गंधहीन होना चाहिये। फिर भी पेयजल में आवश्यक खनिजों की न्यूनतम उपस्थिथिति अनिवार्य है। यह अफसोस की बात है कि इस दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल वैज्ञानिकों का मुख्य लक्ष्य जल प्रदूषकों के विषाक्त गुणों के निपटान की तरफ ज्यादा है। हाल के कुछ नये शोधों में पेयजल के लिये आवश्यक तत्वों की न्यूनतम मात्रा को निर्धारित करने के प्रयास हो रहे हैं। दूषित जल में अनेक हानिकारक तत्व पाये जाते हैं। ये सवास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या पैदा करते हैं। इनमें आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट आदि प्रमुख हैं। इन हानिकारक रसायनों की उपस्थिति जल को विषाक्त बनाती है

कहावत है, जल है तो जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। यह धरती पर समूची मानव सभ्यता का आधार है। जल की कोख में जीवन अस्तित्व में आया तथा विकसित हुआ। इसलिए काव्यात्मक रूप में जल को जीवन का पालना भी कहा जाता है। यदि जल दूषित हो गया तो फिर जीवन में दूषण आना स्वाभाविक है। जल प्रदूषण आज एक गंभीर और भयावह वैश्विक समस्या बन चुका है।

सामान्य शब्दों में जल-प्रदूषण की परिभाषा इस तरह की जाती है कि ''जब जल में दूषित पदार्थों के मिल जाने से उसकी की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है और वह जल मनुष्यों एवं अन्य जीवों केलिए नुकसानदेह हो जाता है, तो इसे 'जल प्रदूषण' कहते हैं।'' जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्यौगिक क्रियाओं से पैदा हुए अपशिष्टों तथा मल-जल (सीवेज) को बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जल स्रोतों (नदियों, झीलों, तालाबों आदि)में विसर्जित कर दिया जाना है। इस-के अलावा भी अनेक कारण हैं जिनसे जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ये विषाक्त रसायन न केवल सतही जल को प्रदूषित कर रहे हैं बल्कि इन हानिकारक रसायनों का भूमिगत जल की गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जिन ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थों क मिल जाने से जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऐसे पदार्थों को 'प्रदूषक' कहते हैं। प्रदूषक कई प्रकार के होते हैं जैसे कि औद्योगिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, पेस्टीसाइड, मलजल, डिटर्जेण्ट, नाभिकीय अपशिष्ट, आदि। ये प्रदूषक स्वच्छ जल में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। इस दूषित जल के सेवन से हैजा, पेचिस, पीलिया जैसी अनेक बीमारियाँ फैलती हैं। गंगा नदी क बारे में विश्वास किया जाता है कि इसमें स्व-शुद्धीकरण क्षमता है। लंबे समय से चली आ रही इस मान्यता का वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं व अन्य रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। नदी के जल में प्राणवायु (ऑक्सीजन) की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है।

बहुमुखी प्रतीभा के धनी ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैनबरी हैंकिन ने यह सिद्ध किया कि गंगा के जल में हैजे की रोकथाम की अनूठी क्षमता है। लेकिन गंगा के तट पर बसे नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा नदी में मिलने से गंगा प्रदूषित होती जा रही है। यह गंभीर चिंता का विषय है। नवीनतम वैज्ञानिक आंकड़े. कहते हैं कि गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश तक गंगा के जल में रोगाणुओं को मारने की क्षमता बरक़रार है। मगर कानपुर और इलाहाबाद में गंगा के जल में जानलेवा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु मौजूद हैं। कोरोना के वैश्विक संकट के समय देश में चल रही महाबन्दी ने

इस बात की पुष्टि कर दी है जब दशकों बाद गंगा, यमुना जैसी नदियाँ पुन: स्वच्छ तथा निर्मल हो गयीं। उनमें मौजूद जलचर साफ दिखायी देने लगे। मछलियाँ तथा डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई तथा कछुए नदी के किनारे बालू पर स्वच्छन्द विचरण करते देखे गए। लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि गंगा का जल स्नान ही नहीं, अपितु पीने योग्य भी हो गया। हमें गंगा सहित देश की सभी नदियों एवं जलस्रोतों के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु काम करना हच्गा। इसक साथ ही वर्षा जल के संग्रहण तथा प्रबन्धन पर ठच्स कदम उठाना होगा तभी भूजल का स्तर बरकरार रह पाएगा। जल संसाधन क मद्देनज़र हम बेहद मुश्किल तथा निर्णायक दौर से गुजर रहे हैं। इसमें आज की बेपरवाही आने वाले कल के लिए संकट का कारण बनेगी।

2020 के बाद कोरोना खत्म हो जायेगा?

बहुतों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि 2020 के बाद कोविड-19 का समापन हो जायेगा। सबों का मानना है कि साल 2020 मानव जीवन के लिये बहुत ही बुरा साल है और यह साल खत्म होगा 2021 प्रारंभ होगा तब कोरोना का खतरा भी खत्म हो जायेगा। खैर ये तो आम लोगों की कष्ट में घिरने के कारण आशावादी सोच है। पर क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्या कोरोना वायरस कैलेंडर और साल के बदलते ही खुद को भी बदल लेगा और संक्रमण से विमुख हो जायेगा? जवाब है नहीं। हम सभी यह बात समझ सकते हैं कि महामारी किसी दिन तिथि या कैलेंडर वर्ष के अनुसार आते जाते नहीं है।

भारत के कुछ राज्यों में हर साल बाढ़ आती है। बिहार और आसाम ऐसे ही राज्य हैं। बाढ़ के बाद महामारी का प्रकोप होता है। वर्तमान में जब विश्व पहले से ही कोरोरा महामारी को झेल रहा है तब बाढ़ के बाद स्थिति और खतरनाक हो सकती है। इसलिये जनता ही खुद को कोरोना से सुरक्षित रखे।

साल 2020 भी चला जायेगा, पर कोरोना भी समाप्त हो जाये ऐसा कुछ नहीं। आज तक विकसित देश भी दिन रात परिश्रम करके भी कोरोना की कोई दवा या वैक्सिन नहीं बना पाये हैं। इसके बनने और सफल होने में कम से कम एक साल लगेंगे। तब तक हमें ये मान कर चलना है कि कोरोना लोगों को तबाह करते रहेगा। आम लोग खुद सतर्क रहें, घरों में रहें, बच कर रहें वही सबसे बेहतर वैक्सिन और दवा है।

हकीकत में साल 2020 के समापन के बाद भी अगर कोरोना की कोई दवा या वैक्सिन नहीं बनती है तो खतरा आज की तरह ही ज्यों का त्यों रहेगा। भारत में भले कोरोना से मौतों का आंकड़ा उतना भयावह नहीं है, पर कोरोना की मार सिर्फ लोगों के आरोग्य पर ही नहीं है बल्कि देश के आर्थिक स्वास्थ्य पर भी है। इसके कारण उद्योग धंधों के चौपट होने से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है।

ऐसे में हम देशवासियों का यह कर्त्व्य बनता है कि हम स्वयं अपनी रक्षा करें, कोरोना से बचाव के लिये सतर्क रहें। हमारी लापरवाही सिर्फ हमें ही संकट में नहीं डालती बल्कि देश को भी नुकसान पहुंचाती है। सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़, बेड से लेकर चिकित्सकों तक की कमी। सरकार पर दबाव और उसके बाद हजारों की दुखद मौतें। साल 2020 ही नहीं जब तक कोरोना का निदान नहीं निकलता तब तक सबों को सतर्क रहना लापरवाही से बचना ही सबसे बेहतर इलाज है।

लॉकडाउन से जामुन के व्यवसाय को नुकसान

अजमेर के जामुन व्यवसाय पर पहले लॉकडाउन, अब मौसम की मार।पीक सीजन में लॉकडाउन के कारण माल बाहर नहीं जा सका। जब थोड़ा खुला है तो बारिश नहीं हो रही

दिल्ली, जयपुर अजमेर सहित उत्तर भारत के तमाम शहरों में हम और आप जो बड़े-बड़े और मीठे जामुन चाव के साथ खाते हैं, वो अजमेर जिले के कुछ गांवों के किसानों की मेहनत का नतीजा हैं। उत्तर भारत में सप्लाई होने वाले जामुन, गोंदा जैसे फलों की मांग का अधिकतर हिस्सा अमजेर जिला पूरी करता है। जिले की पीसांगन पंचायत समिति की चार ग्राम पंचायतें गनाहेड़ा, तनात, तिलोरा और बासेली के 18 गांवों में जामुन की खेती की जाती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन और देरी से हुई बारिश के कारण जामुन किसान मायूस हैं।

जामुन के बाग रखने वाले किसानों का कहना है कि पीक सीजन के वक्त लॉकडाउन था जिसके कारण हमारा माल बाहर नहीं जा सका और अब जब सब थोड़ा खुला है तो बारिश नहीं हो रही। बारिश नहीं होने से जामुन का आकार छोटा हो गया है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में तेज बारिश हुई है, लेकिन अब सीजन ही खत्म होने को आ गया है। गनाहेड़ा में जामुन का व्यवसाय करने वाले मनोहर कहार की पीड़ा भी कुछ ऐसी ही है। मनोहर के पास बाग में जामुन के 20 पेड़ हैं जो उन्होंने 30 हजार रुपए में एक सीजन के लिए ठेके पर लिए हैं। वह बताते हैं कि हमारा जामुन दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित कई शहरों में सप्लाई होता है, लेकिन इस बार हम बहुत कम संख्या में सिर्फ अजमेर और जयपुर तक ही सप्लाई कर पाए क्योंकि लॉकडाउन में हमें जामुन सप्लाई के लिए वाहन नहीं मिल सके। वह आगे बताते हैं, "इस बार हमारा खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। जामुन तोड़ने के लिए 700 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूर आता है। इसके साथ ही एक पेड़ पर पूरे सीजन में करीब 2,500 रुपए खर्चा होता है। इसमें खाद, पानी, केमिकल के खर्चे शामिल होते हैं। इस बार मांग कम होने से हमें बहुत नुकसान हुआ है।

साभार डाउन टू अर्थ

क्या आपदा को विपदा बनने का अवसर दे रहे हैं विश्व के कोविड रिकवरी पैकेज ?

निशान्त सक्सेना

पूरी दुनिया में आपदा को अवसर बनाने की बात हो रही है। लेकिन बात अगर पर्यावरण की हो तो यह आपदा अब विपदा बनती दिख रही है। कम-अज़-कम विविड इकोनोमिक्स की इस ताज़ा रिपोर्ट से तो ये ही समझ आता है।

ग्रीन स्टिम्युलस इंडेक्स नाम की इस रिपोर्ट की मानें तो दुनिया भर में कोविड महामारी के बाद जनता की सेहत और पर्यावरण को बचाने के इरादे से दिए कुल 11.8 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक पैकिज का अधिकांश हिस्सा ऐसे क्षेत्रों में निवेश किया गया है जो लम्बे समय में पर्यावरण के लिए बेहद बुरे साबित होंगे। और तब, स्थिति को संभालना और भी मुश्किल हो चुका होगा। इन आर्थिक पैकिजों की ऐसी प्राथमिकतायें तब हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसी तमाम संस्थाएं सभी देशों को इस विषय में जागरूक करती आयी हैं।

विविड इकोनोमिक्स ने पहले विश्व की 17 अर्थव्यवस्थाओं के कोविड रिकवरी पैकिजों को उनके द्वारा जीवाश्म ईंधन, अक्षय ऊर्जा, और प्रदूषण फ़ैलाने वाले उद्योगों को दिए जाने वाले सहयोग और प्राथमिकताओं के आधार पर समझा। उसके बाद इन देशों की एक रैंकिंग तैयार की गयी जिसे ग्रीन स्टिम्युलस इंडेक्स का नाम दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत इस इंडेक्स में नेगेटिव स्कोर ले कर, चीन और रूस जैसे देशों के साथ खड़ा है। भारत के साथ जो सोलह और देश हैं, वो हैं, चीन, इंडोनेशिया, अमरीका, रूस, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, स्पेन, कोरिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, और युरोपियन यूनियन।

बात भारत की करें को जो कुछ एहम बातें सामने आती हैं, वो हैं..

1. भारत ने COVID 19 जवाब में 266 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज पारित किया है।

2. प्रोत्साहन पैकेज की संरचनाः भारत का प्रारंभिक पैकेज स्वास्थ्य सेवा और कल्याण के लिए समर्थन पर केंद्रित है, लेकिन आगे के फैसलों में व्यवसायों के लिए पर्याप्त समर्थन और कृषि क्षेत्र के लिए लक्षित समर्थन शामिल है।

3. भारत का नकारात्मक सूचकांक स्कोर खराब अंतर्निहित पर्यावरण प्रदर्शन और विशिष्ट हानिकारक उपायों से प्रेरित है जिसमें कोयले के लिए महत्वपूर्ण समर्थन शामिल है। हालाँकि, सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल उपायों की कुछ घोषणाएँ की हैं।

4. भारत की राज्य की खानों से बाजार में कोयला लाने में मदद करने के लिए कोयला बुनियादी ढांचे के लिए भारत का वर $ 6.6 मिलियन का वित्तपोषण।

5. आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र लाभ प्रदान करते हुए ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए वनीकरण कार्यक्रम की दिशा में यूएस $ 780 मिलियन। यह धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (**CAMPA**) कोष के माध्यम से प्रदान की जाती है।

6. भारत अपने व्यापारिक भागीदारों से तेल भंडार की एक रणनीतिक राशि हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है

अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विविड एक्नौमिक्स के वरिष्ठ अर्थशास्त्री, मटो सलाज़ार कहते हैं, ''कोविड की शक्ल में पूरी दुनिया अपनी तरह का ऐसा कुछ पहली बार अनुभव कर रही है। यह बड़ी नाज़ुक स्थिति है। मानव गतिविधियों ने पहले ही पर्यावरण और प्रकृति को नुकसान पहुँचाया हुआ है। और अब इन आर्थिक पैकिजों की प्राथमिकताओं को देख लगता है जलवायु संकट के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।

आगे और देशों के पैकिजों की बात करें तो पड़ोसी मुल्क चीन का रिकवरी पैकिज भी ख़ासा आलोचनीय है और अच्छे बुरे का मिश्रण है जहाँ कुल मिलाकर पैकिज पर्यावरण के लिए बुरा ही साबित होता दिखता है। चीन ने राजकोषीय प्रोत्साहन में कुल यूएस $ 592 बिलियन पारित किया है। स्वास्थ्य देखभाल और कल्याणकारी उपायों के साथ, प्रोत्साहन पैकेज में चीन के बड़े और पर्यावरणीय रूप से गहन औद्योगिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त समर्थन शामिल है। साथ ही, इस पैकिज में कोयला परमिट स्वीकृतियों की गति बढाने की बात है, जो कि 2020 तक कोयले को राष्ट्रीय ऊर्जा खपत के 58 प्रतिशत तक सीमित रखने की सरकार की प्रतिबद्धता के विपरीत है।

अब बात विश्वशक्ति अमेरिका की करें तो वहां भी हालात बुरे ही हैं। अमरीका ने 2.98 ट्रिलियन डॉलर का कुल पैकिज पास किया है। उसका नकारात्मक स्कोर काफी हद तक अपर्याप्त अंतर्निहित पर्यावरण प्रदर्शन, पर्यावरण मानकों के व्यापक प्रसार और बड़े बिना शर्त एयरलाइन खैरात के कारण है। वहां एकमात्र सकारात्मक घोषणा अनुसंधान और विकास के लिए सब्सिडी है। अब बात पर्यावरण अनुकूल आर्थिक पैकिजों की करें तो यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम उम्मीद जगाते हैं। यूरोपीय यूनियन का पैकिज सबसे लुभावना और पर्यावरण अनुकूल है। 830 बिलियन डॉलर के इस पैकिज का 30 प्रतिशत सीधे तौर पर पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के लिए आवंटित है। सबसे अच्छी बात है कि रिकवरी के लिए सस्य देशों को दी जाने वाली राशि इस शर्त के साथ दी जाएगी कि उनके द्वारा उस राशि से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। जर्मनी की बात करें तो उन्होंने अपने रिकवरी पैकिज में अभी 45बिलियन डॉलर का इज़ाफ़ा किया और उसे नाम दिया भविष्य का पैकिज। ये हालाँकि उनके कुल पैकिज का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन इसे पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के लिए रखा गया है। अब तक अमेरिका, रूस, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका ने कोई पर्यावरणीय रूप से सकारात्मक पैकेज नहीं दिया है। जबकि चीन और इंडोनेशिया में विशाल कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए समर्थन उनके सकारात्मक उपायों से आगे निकल जाता है। वहीँ यूरोपियन यूनियन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और यूके ऐसे देशों में से हैं जिन्होंने कई पर्यावरण अनुकूल उपायों के साथ जवाब दिया है। ब्रसेल्स रिकवरी पैकेज संभवतः आज तक का सबसे पर्यावरण के अनुकूल प्रोत्साहन पैकेज है।

इस पूरे इंडेक्स पर विविड एक्नौमिक्स के मटो सलाज़ार बताते हैं, ''घोषित प्रोत्साहन पैकेज सीधे उन क्षेत्रों में खरबों या डॉलर को पंप करेंगे जिनका प्रकृति पर बड़ा और स्थायी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। असलियत यह है कि ग्रीन स्टिमुलस नौकरियों को बचाने और स्थायी विकास सुनिश्चित करने की एक कुंजी है। इस कुंजी का सही प्रयोग होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2020 में 300 मिलियन से अधिक नौकरियों के नष्ट होने की आशंका है। ऊर्जा दक्षता या नवीकरणीय क्षेत्रों में निवेश किए गए प्रति डॉलर जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों की तुलना में कई गुना अधिक नौकरियां पैदा होती हैं।

अब देखना यह है कि इन प्राथमिकताओं के साथ पूरी दुनिया कैसे इन्सान की सेहत, जलवायु परिवर्तन से उसकी सुरक्षा, और आर्थिक विकास में तालमेल बना पाती हैं।

मजदूरों के लिए युद्ध और संघर्ष से ज्यादा बड़ा खतरा हैं जलवायु से जुड़ी आपदाएं

रिचर्ड महापात्रा/ ललित मौर्य

जलवायु से जुड़ी आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि युद्धों से ज्यादा श्रमिकों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही हैं। उपर से महामारी कोविड-19 ने आग में घी का काम किया है। जिसने पहले से ही इन आपदाओं का बोझ सह रहे मजदूरों की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि 2000 के बाद से इन आपदाओं के घटने की दर दोगुनी हो गई है।

2000 के बाद से जलवायु सम्बन्धी आपद-ाओं की दर दोगुनी हो गई है जिसका व्यापक असर श्रमिकों की उत्पादकता पर पड़ रहा है ऊपर से कोविड-19 महामारी ने स्थिति को बद से बदतर बना दिया है। कोविड-19 महामारी ने पूरे श्रम बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चिंतित करती है वह है श्रम उत्पादकता में आ रही गिरावट। जिसका मतलब है कि किसी श्रमिक द्वारा हर दिन किये जा रहे काम में कमी आना। किसी मजदूर द्वारा हर दिया किया जाने वाला काम सीधे तौर पर उसकी रोज की मजदूरी से जुड़ा होता है और उत्पादकता के घटने का सीधा मतलब है मजदूरी का घटना। 2007 से 09 के बीच आए वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से दुनिया पहले ही श्रम उत्पादकता में गिरावट के एक दशक से भी ज्यादा लम्बे दौर से गुजर रही है। ऐसे में कोविड-19 और आपदाओं के बीच आने वाला भविष्य क्या होगा यह बात अर्थशास्त्रियों को चिंतित कर रही है। हालांकि, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में वित्तीय संकट और युद्ध से अधिक बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को श्रम उत्पादकता के लिए खतरा बताया है। साथ ही इस रिपोर्ट में कोविड-19 जैसी महामारियों को भी इन आपदाओं में शामिल किया है। जिसका असर श्रम उत्पादकता और मजदूरों के भविष्य के लिए और दुखदायी होगा।

इस रिपोर्ट ग्लोबल प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स, ड्रा-इवर्स, और पॉलिसीज" में पहली बार कोविड-19 के श्रम उत्पादकता पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया है। इसमें श्रम उत्पादकता पर असर डालने वाली अनेक घटनाओं जैसे युद्ध, संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के असर का तुलनात्मक विश्लेषण किया है। जिसके निष्कर्ष के अनुसार भले ही युद्ध और संघर्ष के श्रमिक उत्पादकता पर गंभीर असर पड़ रहें हैं। पर जलवायु आपदाओं की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि पहले की तुलना में कहीं ज्यादा श्रम उत्पादकता और बाजार पर असर डाल रही हैं। जोकि युद्ध और संघर्ष की तुलना में कहीं ज्यादा है।

रिपोर्ट के अनुसार हालांकि युद्ध के कारण पूंजी और उत्पादकता से जुड़े कारकों पर गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले असर पड़ते हैं। पर जलवायु से जुड़ी आपदाओं के बढ़ने से श्रमिक उत्पादकता पर व्यापक असर पड़ रहा है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो उसके अनुसार 1960 से 2018 के बीच आई प्राकृतिक आपदाओं की संख्या युद्धों की तुलना में 25 गुना और 2008 जैसे वित्तीय संकटों से 12 गुना ज्यादा थी। वहीं प्राकृतिक आपदाओं में विशेषकर जलवायु संबंधी आपदाएं जैसे चक्रवात और चरम मौसम की घटनाएं बार-बार आघात कर रही हैं। जिससे ने केवल अर्थव्यवस्था बल्कि श्रम उत्पादकता पर भी व्यापक असर पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं में विशेषकर जलवायु से जुड़ी घटनाएं दुनिया भर में बढ़ती जा रही हैं। इनके घटने की दर 2000 के बाद से लगभग दोगुना बढ़ चुकी है। जबकि सभी प्राकृतिक आपदाओं में जलवायु संबंधी आपदाओं का हिस्सा करीब 70 फीसदी था। और वो कोविड-19 महामारी जैसी जैविक आपदाओं की तुलना में दो बार घटित हुई हैं। इस अवधि के दौरान, जलवायु से जुड़ी आपदाओं ने श्रम उत्पादकता में 0.5 फीसदी सालाना की दर से कमी की है। यह श्रम उत्पादकता पर युद्ध के प्रभाव का लगभग पांचवां हिस्सा है। लेकिन यदि जलवायु से जुड़ी आपदाओं की संख्या को देखें तो वो इतनी अधिक हैं कि उनके द्वारा पड़ने वाला संयुक्त असर श्रम उत्पादकता में बड़े नुकसान का कारण बनता है। इससे भी बढ़कर इन घटनाओं का असर श्रम उत्पादकता पर लम्बे समय तक रहता है, जो ज्यादा कष्टकायी होता है।

श्रम उत्पादकता में 7 फीसदी की कमी के लिए जिम्मेवार हैं जलवायु से जुड़ी आपदाएं

रिपोर्ट के अनुसार तीन वर्षों में जलवायु से जुड़ी इन विनाशकारी आपदाओं ने श्रम उत्पादकता में लगभग 7 फीसदी की कमी की है। जिससे कुल उत्पादकता में भी कमी आई है। इन आपदाओं से वित्तीय संकट और युद्ध जैसी घटनाओं में भी वृद्धि होती है। जो श्रम उत्पादकता को भी प्रभावित करती हैं। इस तरह यह आपदाएं श्रम उत्पादकता में कमी लाने वाली अन्य घटनाओं को भी हवा देती हैं। महामारी जैसी जैविक आपदाओं से भी श्रम उत्पादकता में भारी कमी आई है। पिछले दो दशकों में, हमने चार प्रमुख महामारियों - सार्स, मर्स, इबोला और जीका के असर को झेला है। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार इन आपदाओं के घटने के तीन साल बाद भी श्रम उत्पादकता में 4 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

यदि पिछली घटनाओं के आधार पर देखें तो कोविड -19 महामारी श्रम उत्पादकता पर बहुत गहरा असर डालेगी। यह महामारी अब तक की सबसे ज्यादा व्यापक महामारी है। जिसका असर दुनिया के लगभग हर देश पर पड़ा है। अनुमान है कि इसके कारण दुनिया के 90 फीसदी देशों में प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी। दुनिया भर पर असर करने के कारण महामारी पिछली सभी आपदाओं से ज्यादा विनाशकारी होगी। साथ ही इसको रोकने के लिए जो लॉकडाउन और सामाजिक दूरी जैसे उपायों को अपनाया गया है उसका एक व्यापक असर श्रमिकों की उत्पादकता और अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा।

जलवायु परिवर्तन का दुनिया पर असर पड़ा है, हरियाली इस संकट का समाधान कर सकती है : अमित शाह

नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन का दुनिया पर असर पड़ा है और केवल हरियाली ही इस संकट का समाधान कर सकती है। कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी को भी प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए बल्कि इसके साथ सहयोग करना चाहिए। गृह मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, शाह ने छह इको-पार्क और पर्यटन स्थलों की आधारशिला रखी। पौधारोपण कार्यक्रम भारत भर के दस कोयला और लिग्नाइट समृद्ध राज्यों के 38 जिलों में 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चलाया गया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का दुनिया पर असर पड़ा है और केवल हरियाली ही इस संकट का समाधान है।

उन्होंने कहा, ''भारतीय विरासत का मुख्य मंत्र है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए न कि उनका दोहन करना चाहिए। हमने इस सिद्धांत की उपेक्षा की जिससे ओजोन के परत में क्षति हुई और ओजोन छिद्र बने जिसके कारण वैश्विक तापमान बढ़ा और जलवायु परिवर्तन हो रहा है।'' गृह मंत्री ने कहा कि इस समस्या का केवल एक समाधान है और उनमें से एक का वर्णन 'पुराणों' में मिलता है कि वृक्ष मानवता के हितैषी हैं और केवल हरियाली ही लोगों को इस संकट से उबार सकती है।

आइआइटी खड़गपुर ने दो हजार रूपये में बनाये कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आ-ईआईटी) खड़गपुर ने एक ऐसी कोविड-19 रेपिड टेस्टिंग मशीन तैयार की है, जो आरटी-पीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन- पोलीमरेज चेन रिएक्शन) का विकल्प बन सकती है। केवल 2,000 रुपए की लागत से तैयार इस मशीन से महज 400 रुपए में कोरोनावायरस की जांच की जा सकती है। बड़े स्तर पर उत्पादन होने पर इसकी लागत में और कमी आ सकती है।

इस मशीन से होने वाली जांच के नतीजे आरटी-पीसीआर की जांच से शत प्रतिशत मिलते हैं। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि यह एक पोर्टेबल डि-वाइस है, जिसे दूरदराज के इलाकों में ले लाकर जांच की गति तेज की जा सकती है। आ-ईआईटी खड़गपुर का दावा है कि यह दुनिया पहली ऐसी मशीन है जो प्रयोगशाला और चारदीवारी से निकलकर बड़े पैमाने में जांच करने में सक्षम है।

अगले 30 सालों में चारगुणा यानि1,400 करोड़ हो जाएंगे कूलिंग उपकरण

एल मौर्य

दुनिया भरों में घरों और दफ्तरों को ठंडा रखने के लिए कूलिंग उपकरणों की जरुरत बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिन-प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है जिससे निपटने के लिए कूलिंग उपकरणों की मांग भी बढ़ रही है आज यह उपकरण सिर्फ लग्जरी ही नहीं बल्कि जरुरत भी बनते जा रहे हैं बात चाहे घरों और दफ्तरों को ठंडा रखने की हो या फिर सामान को ताजा बनाये रखने की या फिर दवाओं को सुरक्षित रखने की, हर जगह इनकी जरुरत पड़ती है

अनुमान है कि दुनिया भर में इस समय घरों और जरुरी सामान ठंडा करने के लिए 360 करोड़ उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है जोकि अगले 30 सालों में बढ़कर 1,400 करोड़ हो जाएंगे हालांकि, कई एयर कंडीशनिंग यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं जोकि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जलवायु के लिए हजारों गुना ज्यादा हानिकारक होती है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अनुकूल कूलिंग उपकरणों की मदद से उत्सर्जन में भारी कटौती की जा सकती है जोकि जलवायु में आ रहे बदलावों की गति को कम कर सकती है यूएनईपी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा संयुक्त रूप से किये गए इस अध्ययन के अनुसार यदि अकेले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) जैसे रेफ्रिजरेंट के उपयोग में कटौती कर दी जाए, तो इससे तापमान में हो रही 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को सदी के अंत तक रोका जा सकता है

एयर कंडीशनर की दक्षता में इजाफा करके 46,000 करोड़ टन ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोका जा सकता है जोकि 8 सालों में उत्सर्जित होने वाली कुल ग्रीनहाउस गैसों के बराबर है बस इसे हासिल करने के लिए अगले 4 दशकों तक कूलिंग उपकरणों की दक्षता को आज के मुकाबले में दोगुना करना होगो जिसके परिणामस्वरूप 2050 तक 13,00,000 मेगावॉट बिजली की बचत की जा सकती है यह उतनी ऊर्जा जितनी है भारत और चीन दोनों देशों में मौजूद

थर्मल पावर प्लांट मिलकर साल भर में पैदा करते हैं यह करीब 2,17,28,584 करोड़ रुपए (290,000 करोड़ डॉलर) की बचत करने जितना होगा। ऐसे में तेजी से बढ़ते कूलिंग उपकरणों की मांग ने केवल एचएफसी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में वृद्धि करेगी बल्कि साथ ही इनके लिए बड़ी मात्रा में बिजली की भी जरुरत पड़ेगी जोकि फॉसिल फ्यूल पर निर्भर होगी ऐसे में इससे तापमान में हो रही वृद्धि में और इजाफा होगो जिससे बचने के लिए इन कूलिंग सिस्टम्स की मांग और बढ़ेगी इस तरह से यह बढ़ते तापमान के एक चक्र का रूप ले लेगी।

रिपोर्ट के अनुसार देशों के पास पहले ही ऐसे कई उपाय हैं जिससे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है जैसे किगाली एग्रीमेंट और मोंट्रियल प्रोटोकॉल में पहले ही ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली एचएफसी के उपयोग में कटौती करना शामिल है साथ ही उपकारों के लिए ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी मानक, घरों और बिल्डिंग्स को इस तरह बनाना की कूलिंग उपकरणों की जरुरत कम से कम पड़े साथ ही जिन वस्तुओं और खाद्य पदार्थों के लिए कूलिंग सिस्टम की जरुरत पड़ती है उसकी सप्लाई चेन को अधिक बेहतर और दक्ष बनानो जिससे कूलिंग की जरुरत कम पड़े।

यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक इनगर एंडरसन के अनुसार, "दुनिया पहले ही कोविड-19 जैसी महामारी का सामना कर रही है और देश अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में उनके पास जलवायु परिवर्तन को कम करने, प्रकृति की रक्षा करने और बुद्धिमानी से अपने संसाधनों का उपयोग करने का अवसर है। ऐसे में एक कुशल और दक्ष कूलिंग सिस्टम इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिक दक्ष और बेहतर एयर कंडीशनिंग के अन्य लाभ भी होंगे जैसे कि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों के लिए बेहतर कूलिंग सिस्टम, हवा की गुणवत्ता में सुधार और भोजन और अन्य जरुरी सामान को ख़राब होने से बचाया जा सकेगो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र और आईईए के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना जरुरी है साथ ही एचएफसी के उपयोग में भी कटौती करनी होगी और ऐसे करने के लिए कठोर मानकों की जरुरत है अध्ययन के अनुसार यह कदम वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।

सीसीएल ने हातमा बस्ती में 40 आरसीसी डस्टबिन लगाया

रांची : ''स्वच्छ भारत अभियान'' का मुहिम कोविड-19 का प्रभाव को कम करने के साथ-साथ स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीएमडी, सीसीएल गोपाल सिंह के मार्गनिर्देशन में निरंतर प्रयासरत किया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए हातमा बस्ती, कांके रोड, रांची में 40 (चालीस) आरसीसी डस्टबिन की स्थापना किया गया है। सभी डस्टबीन प्रमुख स्थानों, चौक चराहों, गली, आवास के सामने बस्ती के निवासी एवं आमजन के उपयोग के लिए लगाया गया है जिसे बस्तीवासी कचरे का संग्रहण और निपटान उचित स्थान पर कर सकेंगे जिससे स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।

निदेशक (कार्मिक) विनय रंजन के नेतृत्व में कोरोना महामारी की इस संकट के समय में भी सीएसआर के अंतर्गत समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए सभी डस्टबिनों की स्थापना सीसीएल ने ग्रामवासियों के सहयोग से किया है।

ऊष्णकटिबंधीय वनों में हर साल 10 करोड़ से अधिक बार गिरती है बिजली

बढ़ते जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम की घटनाओं के कारण बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं।2018 में दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में केवल 13 घंटों के अंदर 36,749 बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गई थी। इसी माह केवल बिहार में बिजली गिरने से 147 लोगों की जान चली गई। बिजली गिरने से लोग ही प्रभावित नहीं होते है, बल्कि वनों पर भी इसका भयानक असर होता है। वनों मे बिजली गिरने को लेकर पनामा के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया है। बिजली सालाना लगभग 83.2 करोड़ ऊष्णकटिबंधीय पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है, इनमें 19.4 करोड़ पेड़ नष्ट हो जाते हैं पनामा के स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसटीआरआई) के शोधकर्ताओं ने एक नक्शा प्रकाशित किया है, जो ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बिजली गिरने वाले स्थानों को दिखाता है। उपग्रह के आंकड़ों के आधार पर, उन्होंने अनुमान लगाया हैं कि प्रत्येक वर्ष भूमि पर 10 करोड़ से अधिक बार बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। इस तरह की घटनाएं कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जंगलों और अन्य पारिस्थितिकी प्रणालियों को बदल रही हैं। यह अध्ययन ग्लोबल चेंज बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। एसटीआरआई के पोस्ट-डॉक्टरल फेलो इवान गोरा ने कहा बिजली गिरने से जंगलों के बायोमास (जैव ईंधन) को स्टोर करने की क्षमता प्रभावित होती है क्योंकि बिजली सबसे बड़े पेड़ों पर प्रहार करती है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया वन महोत्सव 2020' का ऑनलाईन शुभारंभ

संवाददाता

सीसीएल में ऑनलाईन के माध्यम से ईको पार्क का शिलान्यास

रांची : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास से पौधारोपण कर वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के साथ सीसीएल सहित कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों एवं लिग्नाईट कम्पनियों में 'वन महोत्सव 2020' का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, कोयला सचिव अनिल कुमार जैन एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित थे। सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का लाईव टेलिकास्ट किया गया जिसमें सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये जन-प्रतिनिधिगण, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, कर्मी सहित स्टेकहोल्डर्स ने भाग लिया।

सीसीएल मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में माननीय सांसद (रांची) संजय सेठ, माननीय सांसद (गिरिडीह) चन्द्रप्रकाश चौधरी, माननीय सासंद (चतरा) सुनिल कुमार सिंह सहित सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने संयुक्त रूप से 'कायाकल्प वाटिका'' का उद्घाटन किया। सभी माननीय सांसद, सीएमडी, सीसीएल एवं निदेशकगण ने 'कायाकल्प वाटिका' में पौधारोपण किया।

इस अवसर पर निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री भोला सिंह सहित विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष एवं कर्मी सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय सहित कोयला परिवार को शुभकामनाएं देते हुये कहा कि स्वतत्रंता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान की शुरूआत की जा रही

है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दुनिया जलवायू परिवर्तन का सामना कर रही है और धरती माता को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना हम सभी का कर्तव्य है।

कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश में कोयला भंडार प्रचुर मात्रा में है और देश को कोयले के आयात करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने कहा कि उनके मार्गनिर्देशन में कमर्शियल माइनिंग की शुरूआत की गयी है। और हमारा लक्ष्य है कि कोयला का आयात आने वाले समय में शून्य हो जाय। मंत्री महोदय ने बताया कि कोल इंडिया को वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक बिलियन टनकोयला उत्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान में स्थानीय जलवायु एवं आवश्यकता को देखते हुये चयनित स्थान पर पौधारोपण किया जा रहा है।सीएमडी गोपाल सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री, माननीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड, माननीय सासंद एवं सीसीएल के श्रमिक प्रतिनिधिगण एवं स्टेकहोल्डर्स को साधुवाद देते हुये कहा कि सीसीएल वृहद स्तर पर ईको पार्कका निर्माण एवं वृक्षारोपण समयबद्ध रूप से कर रहा है जिससे झारखंडवासी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि ईको पार्क निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों से लेकर बुजूर्गों तक सभी लाभान्वित हो। गोपाल सिंह ने कहा कि सीसीएल कोयला कंपनी है और इस नाते सीसीएल का पर्यावरण के क्षेत्र में दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। सीसीएल न सिर्फ कोयला उत्पादन कर देश की उर्जा आवश्यकता को पूरा कर रहा है बल्कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर निदेशक (कार्मिक) विनय रंजन ने वृक्षारोपण अभियान की शुरूआत के लिए शुभकमानाएं दी और आज के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दिया। यह आयोजन कोयला/लिग्नाइट के भंडार वाले 10 राज्यों के 38 जिलों में फैले 130 से भी अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

कार्यक्रम के दौरान सीसीएल कमांड क्षेत्रों में 12 'ईको पार्क' का शिलान्यास किया गया। यह सभी ईको पार्क सीसीएल के कथारा, बोकारो एवंकरगली, पिपरवार, ढोरी, रजरप्पा, बरका-सयाल, हज़ारीबाग, कुजू, एनके, मगध आम्रपाली, अरगड्डा एवम मुख्यालय में विकसित किया जायेगा। सभी 11 'ईको पार्क' 317 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है जिसमें विभिन्न जैव विविधता, मृदा संरक्षण एवं पर्यावरण संबंधी अन्य गतिविधियों को आधुनिकतकनीकी के माध्यम से विस्तारित किया जायेगा। आधुनिक तकनीकी का उपयोग जैसे सीड बॉल का प्रयोग कर पौधा प्लांटेशन किया जायेगा। सीसीएल में लगभग 1 लाख पौधारोपण एवं वितरण किया जा रहा है।

विभागाध्यक्ष (वन एवं पर्यावरण) सौमित्र सिंह एवं उनकी टीम का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय योगदान रहा ।

बकरी पालन:हर मौसम मे आमदनी का सहारा

एक या अधिक पशुओं के समूह को कृषि संबंधी परिवेश में भोजन ,रेशे तथा उनमें प्राप्त होने वाली सामग्रियां के लिए पालतू बनाया जाता है जिसे पशुधन कहा जाता है। पशुधन आमतौर पर जीविका अथवा लाभ के लिए पाले जाते हैं। पशुओं को पालना आधुनिक कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन आजकल शहरो में भी पशु पालन किया जाने लगा है तथा उनका व्यवसाय किया जाता है तथा उनसे प्राप्त आमदनी का प्रयोग अपनी निजी उपयोग के लिए किया जाता है।

शहरो मे लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि बकरियों को अपने छतो में रखते हैं । दुमका जिले के गिधनी छेत्र में एक घर मे ऐसा देखने को मिला, जहां लोगों ने दस या पंन्द्रह बकरियों को पाले हैं और उन्हें अपनी सुविधानुसार उन्हें छतो में रखते हैं और वही पर उन्हें चारा दिया जाता है और कभी - कभी चराने के लिए भी खुले स्थानों ले जाया जाता है। इसलिए उनलोगों ने अपने बकरियों पर रंगों का निशान बनाये हुवे हैं ,ताकि उनके बकरियों को पहचानने में आसानी हो और दूसरे बकरियों से अलग दिख सके और दूसरे बकरियों के झुंड में भी खोजने में आसानी होती है ।ग्रामीण इलाकों में बकरी पालन सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाता है । जिससे बाजार की कोई समस्या नहीं रहती है। बकरी छोटा जानवर होने के कारण इसके रख - रखाव में लागत भी कम होती है। सूखा पड़ने के दौरान भी इसके खाने का इंतिजाम सरलता से हो जाता है। इसकी देखभाल महिलाएं एवं बच्चे आसानी से कर सकते हैं और साथ ही जरूरत भी पूरी की जा सकती है। जरूरत के समय बकरियों को बेचकर आसानी से नकद पैसा प्राप्त किया जा सकता है।

बकरी पालन करने के लिए किसी भी प्रकार की तकनीकी की जरूरत नहीं होती है। बकरी पालन ही आसानी से जा सकने वाला कम लागत का अच्छा व्यवसाय है।

एनि: पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग रांची विश्वविद्यालय

संजय सेठ ने सीएमपीडीआई का दौरा किया सीएमपीडीआइ के कार्यों की सराहना की

रांची : लोकसभा सांसद संजय सेठने 23 जुलाई को सीएमपीडीआई का दौरा किया। इस मौके पर संस्थान के कॉफ्रेंस हॉल में उनके समक्ष सीएमपीडीआई द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति के माध्यम से सीएमपीडीआई द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं गतिविधियों से उनको अवगत कराया गया।

इस अवसर पर संजय सेठ ने सीएमपीडीआई द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की एवं कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी भी इच्छा थी कि रांची स्थित सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी लूं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सीएमपीडीआई प्रबंधन को जब भी हमारी सहायता की आवश्यकता महसूस हो, बेहिचक हमारी मदद ले सकते हैं। संजय सेठ, ने सीएमपीडीआई में कोल इंडिया द्वारा आयोजित किए गए ''वृक्षारोपण अभियान'' का उद्घाटन फलदार पौधारोपण कर किया। इस अवसर परसीएमपीडीआई के अध्यक्ष - सह -प्रबंध निदेशक एस0 सरन, निदेशक (तकनीकी/आरडीएंडटी) श्री आर0एन0 झा एवं निदेशक (तकनीकी/पीएंडडी)ए0के0 राणा सहित महाप्रबंधक / विभागाध्यक्षगण ने भी पौधारोण किया। ज्ञातव्य हो कि ''गोईंग ग्रीन इनीसियेटिव'' के तहत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ सभी सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सघन वृक्षारोपण अभियान-2020 चलाया जा रहा है। इसके तहत सीएमपीडीआई (मुख्यालय) तथा इसके क्षेत्रीय संस्थानों में वृक्षारोपण किया गया। मौके पर सीएमपीडीआई में वृक्षारोपण के अलावा फलदार तथा औषधीय पौधे भी वितरित किए गए।

एसोचैम का नॉलेज मैनेजमेंट वर्चुअल मीट

रांची : प्रौद्योगिकियों और वैश्विक कनेक्टिविटी में तीव्र प्रगति हमारे चारों ओर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को तेजी से बदल सकती है। कम उत्सर्जन और कचरे के साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए। व्यवसायों और सरकारों द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग का उपयोग करने और पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ इसे संरेखित करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। भरत जायसवाल ने ये बाते कहीं । उन्होंने कहा कि एसोचैम एक जिम्मेदार चैंबर है जो इसे पहचानता है और उसी के लिए काम भी कर रहा है।

इस महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एसोचैम ने एक नॉलेज मैनेजमेंट वर्चुअल मीट सस्टेनेबिलिटी के आयोजन का प्रस्ताव रखा था- एक ड्रेस रिहर्सल कोविड-19 दवे फॉरवर्ड चैलेंजिस एंड अपॉर्चुनिटी यह आयोजन भरत जायसवाल क्षेत्रीय निदेशक, एसोचैम के सत्र की शुरूआत के साथ शुरू हुआ।

पंकज मल्हान, अध्यक्ष, झारखंड राज्य विकास परिषद और सीईओ स्टील बिजनस वेदांत ने स्वागत भाषण और स्थिरता पर अपना बहुमूल्य विचार दिया।सत्र की अध्यक्षता मनु सेठ, अध्यक्ष, झारखंड राज्य पर्यावरण विकास परिषद और सीईओ, स्पीकिंग माइंडज़ इंक ने किया।सुश्री राधिका शर्मा, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक ने बताया कि जलवायु नीति, शक्ति सतत ऊर्जा वायु गुणवत्ता और वायु प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित कर हम उद्योगों की मदद से कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए।

कम लागत में सालोभर आमदनी का जरिया : बेबीकॉर्न की खेती

.....पेज एक का शेष

पर बेबीकॉर्न की खेती से जोड़ा गया है. इस वर्ष खरीफ मौसम में रांची जिले के चान्हो प्रखंड के कुल्लू, कजंगी एवं बियासी गाँवों के 60 आदिवासी किसानों के कुल 30 एकड़ भूमि में तथा कांके प्रखंड के जिद्दू गाँव के 11 आदिवासी किसानों के कुल 5 .5 एकड़ भूमि में अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण कराया गया

परियोजना अन्वेषक डॉ. मणिगोपा चक्रवर्ती

है. इससे पहले 60 आदिवासी किसानों को प्रशिक्षण के दौरान बेहतर खेती हेतु वर्मी कम्पोस्ट बेड भी बांटा गया.

शस्य वैज्ञानिक (मक्का) डॉ सीएस सिंह बताते है कि शहरों में बेबीकॉर्न की काफी मांग है, जबकि इसका बाजार सीमित है. इसकी खेती से जुड़े किसान सालोभर बेबीकॉर्न की खेती से निरंतर सप्लाई द्वारा बेहतर बाजार लाभ ले सकते है. इसके लिए किसानों को खेतों को 4 भागों में बाँटकर 15-15 दिनों के अंतराल में बुवाई करनी चाहिए. दिसम्बर एवं जनवरी महीने को छोड़कर सालोभर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है. बेबीकॉर्न की खेती किसानों को उच्च आय का अवसर, रोजगार का साधन और निर्यात की संभावनाओं को प्रदान करने में सहायक है.

बेबी कॉर्न (मक्का) एक स्वादिष्ट आहार

अब यह आमजन के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रोल का खाद्य आहार है। इस–ाके साथ ही इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में पाए जाने वाले खनिज की मात्रा के बराबर होती है। बेबी कॉर्न के भुट्टे, पत्तों में लिपटे होने के कारण कीटनाशक रसायन से मुक्त होते हैं। स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होने के कारण इसे एक आदर्श पशु चारा फसल भी माना जाता है। हरा चारे में लैक्टोजेनिक गुण के कारण यह दुधारू मवेशियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है.

बेबी कॉर्न की फसल

मक्का के अपरिपक्व भुट्टे को बेबी कॉर्न कहा जाता है, जो सिल्क की 1-3 सेमी लंबाई वाली अवस्था तथा सिल्क आने के 1-3 दिनों के अंदर तोड़ लिया जाता है. बेबी कॉर्न की फसल रबी में 110-120 दिनों में, जायद में 70-80 दिनों में तथा खरीफ के मौसम में 55-65 दिनों में तैयार हो जाती है।

बेबी कॉर्न की विदेशों में मांग

बेबी कॉर्न की खेती विश्व में सबसे अधिक थाईलैंड एवं चीन में की जाती है. विकासशील देशों जैसे एशिया-प्रशांत क्षेत्रों में भी बेबीकॉर्न खेती की तकनीक को बढ़ावा देने की काफी गुंजाइश है. भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तरप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय तथा आंध्रप्रदेश में की जा रही है. झारखण्ड राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफी फायदेमंद हो सकती है. प्रदेश में आमतौर पर धान और गेहूं कृषि प्रणाली में जायद की फसल के रूप में गरमा मूंग लिया जाता है. जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते हैं. गरमा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो लाभांश की दृष्टि से यह किसान के लिए फायदेमंद नहीं होती है. उस परिस्थिति में अगर किसान बेबीकॉर्न की वैज्ञानिक खेती करते हैं तो काफी लाभ की संभावना है.

बेबी कॉर्न भुट्टे का उपयोग

बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है। इसे कच्चा या पकाकर खाया जाता है। कई प्रकार के व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पास्ता, चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कढ़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, पकौड़ा, सब्जी, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा एवं खीर आदि. इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे के लिए किया जाता है, जो कि बहुत पौष्टिक है। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे को अच्छे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

बेबी कॉर्न की श्रेष्ठ प्रभेद/प्रजाति का चयन

बेबी कॉर्न की प्रजाति का चयन करते समय भुट्टे की गुणवत्ता को ध्यान में रखना चाहिए। भुट्टे के दानों का आकार और दानों का सीधी पंक्ति में होना चाहिए. साथ ही अगेती परिपक्व (55 दिन) वाली तथा एक समान भुट्टे पकने वाली प्रजाति जो मध्यम ऊंचाई की हों, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए. भारत में पहला बेबी कॉर्न प्रजाति वीएल-78 है. इसके अलावा एकल क्रॉस हाईब्रिड एचएम-4 देश का सबसे अच्छा बेबी कॉर्न हाइब्रिड है. साथ ही वीएन-42, एचए एम-129, गोल्डन बेबी (प्रो-एग्रो) का भी चयन बेबी कॉर्न की खेती के लिए कर सकते हैं.

बेबी कॉर्न खेती : उत्पादन तकनीक और मृदा की तैयारी

स्वीटकॉर्न और पॉपकॉर्न की तरह ही बेबी कॉर्न की खेती के लिए मृदा की तैयारी और फसल प्रबंधन किया जाता है। इसकी खेती की अवधि केवल 60-62 दिनों की होती है जबकि अनाज की फसल के लिए यह 110-120 दिनों की होती है। इसके अलावा कुछ और विभिन्नताएं

शस्य वैज्ञानिक (मक्का) डॉ सीएस सिंह

हैं, जैसे झंडों (नर फूल) को तोडना, भुट्टों में सिल्क (मोंचा) आने के 1-3 दिन में तोडना।

बेबी कॉर्न के लिए खेत की तैयारी और बुवाई का तरीका

बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की तीन से चार बार जुताई करने के बाद 2 बार पाटा चलाना चाहिए, जिससे सरपतवार मर जाते हैं और मृदा भुरभुरी हो जाती है .इस फसल में बीज दर लगभग 30 किग्रा प्रति हैक्टेयर होती है .बेबी कॉर्न की खेती में पौधे से पौधे की दूरी 15 सेमी और पौधे की पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेमी होनी चाहिए .इसके साथ ही बीज को 3-4 सेमी गहराई में बोना चाहिए। मेड़ों पर बीज की बुवाई करनी चाहिए और मेड़ों को पूरब से पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए।

राज्य के 5 जिलों में सामान्य तथा 19 जिलों में कम बारिश की स्थिति में किसानों को बीएयू कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

विषम स्थिति में धान की कम अवधि वाली किस्मों की सीधी बोआई करें

डॉ. एम. एम. यादव

मौसम विभाग ने 01 जून से 20 जुलाई तक वर्षापात की स्थिति के आकलन में राज्य में सामान्य से 13 प्रतिशत कम बारिश होने तथा प्रदेश के 24 जिलों में से मात्र 5 जिलों में सामान्य बारिश की बात कही है. शेष 19 जिलों में औसत से कम बारिश होने तथा 5 जिलों को स्कैटी क्षेत्र के रूप में उभरने की बात कही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान में झारखण्ड में मानसून सक्रिय होने की बात कही गई है।

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा तहत एग्रोमेट एडवाइजरी

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम एवं पर्यावरण विभाग ने किसानों के लिए लगातार एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन जारी कर रहा है. ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कार्यक्रम अधीन इस बुलेटिन में अगले 4 - 5 दिनों तक आकाश में बादल छाये रहने तथा कहीं - कहीं छिटपुट तो कही हल्की वर्षा की संभावना जताई है. इस बारे में विभाग के अध्यक्ष डॉ. ए वदूद ने बताया कि एडवाइजरी में किसानों को विभिन्न सब्जियों/फसलों के खेतों में जल निकास के लिए बनी नालियों को सुदृढ़ रखने तथा खर - पतवार नियंत्रित रखने के लिए निकाई - गुड़ाई अवश्य करने का परामर्श दिया गया है. बरसात के दिनों में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम देखते हुए करने तथा दवा के घोल में सेंडोविट या टीपोल (5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर घोल) का प्रयोग करने को कहा गया है. सेंडो-विट या टीपोल के अभाव में दवा के घोल को साबुन के पानी में तैयार करने की सलाह दी है. इससे दवा का घोल चिपचिपा हो जाता है तथा हल्की वर्षा के बावजूद पौधे से दवा पूर्णतया धूलने से बचाव होगा.

बारिश में कमी एवं मानसून की मौजूदा स्थिति में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

राज्य में बारिश में कमी एवं मानसून की मौजूदा स्थिति में बीएयू के जाने-माने शस्य विशेषज्ञ एवं डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने धान फसल की रोपाई में देरी होने की बात कही है. उन्होंने बहुत या कम बारिश की स्थिति में किसानों को जुलाई व अगस्त महीने तक धान की रोपाई करने को कहा है. किसानों को धान रोपा वाले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को खुला छोड़ने तथा खेतों के मेढ़ को दुरूस्त करने की जरूरत बताई है. ताकि खेतों में बढ़िया जल-जमाव हो सके और खेतों में खर-पतवार भली - भांति सड़ जाए.

धान बिचड़ा का प्रबंधन : धान का बिचड़ा 30 दिनों का होने और खेतों में कादो करने लायक पानी जमा नहीं होने की स्थिति में, आगामी दिनों में ऊपरी जमीन से वर्षा के पानी का बहाव से रोपा खेतों में पानी जमाकर रोपा शुरू करने को कहा. उन्होंने एक महिना से पुराना बिचड़े के ऊपरी 10 से. मी. हिस्सा को काटकर तथा बिचड़ों की जड़ को 2 ग्राम डीएपी एवं 2 ग्राम एमओपी प्रति लीटर घोल में डालकर रातभर रखकर सुबह धान का रोपा करने की सलाह दी. धान का बिचड़ा उपलब्ध या तैयार नहीं होने की स्थिति में किसानों को धान की सीधी बोआई करने को कहा. इसमें कम अवधि वाली किस्मों में बिरसा विकास धान - 110, बिरसा विकास धान -111, वंदना, ललाट, नवीन, सहभागी, आईआर - 64 (डीआरटी - 1) में से किसी एक किस्म का चुनाव कर बोआई करने को कहा. सीधी बोआई के लिए एक एकड़ में 40 किलो धान बीज का प्रयोग करने को कहा. साथ ही खेतों में खर-पतवार नियंत्रण के लिए बोआई के 2 - 3 दिनों के बाद खर-पतवार नाशी दवा प्रेटिलाक्लोर का 4 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करने को कहा है.

परती ऊपरी जमीन में खेती : आगामी वर्षापात की स्थिति में ऊपरी जमीन परती रह जाने पर कम अवधि एवं कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों में अरहर, उरद, ज्वार एवं मडुआ की बोआई करने को कहा. इनकी बोआई मेढ़ बनाकर ही करनी चहिए फसल का अंकुरण सामान रूप से नहीं होने की स्थिति में पुनः बोआई तथा एक ही जगह पौधों की संख्या ज्यादा होने पर उसे उखाड़कर खाली जगह पर लगाना ठीक होगा. फसल बोआई के 15 दिनों के बाद खेतों में खर-पतवार का नियंत्रण जरूरी करना चाहिए.

मक्का विशेषज्ञ की सलाह: मक्का विशेषज्ञ डॉ मणिगोपा चक्रवर्ती ने मौसम की स्थिति के आधार पर मकई की खेती में कम अवधि वाली (80 - 90 दिनों में तैयार होने वाली) किस्मों में बिरसा मकई -1, बिरसा विकास - 2, प्रिया एवं विवेक में से किसी किस्म की सीधी बोआई मेड़ बनाकर ही करने को कहा है. एक एकड़ में मकई की बोआई के लिए 8 किलो ग्राम बीज का प्रयोग करने तथा खर-पतवार नियंत्रण के लिए बोआई के 2 - 3 दिनों के बाद खर-पतवार नाशी दवा अट्राजीन का 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करने को कहा।

मृदा वैज्ञानिकों की सलाह :बीएयू के मृदा वैज्ञानिकों ने बोआई के पहले खेतों की मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए खेतों के कतार में 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बुझा चुना या डोलोमाईट का प्रयोग से अधिक उपज ली जा सकती है. दलहनी फसल जैसे अरहर, उरद, मूँग एवं सोयाबीन के बीज को राईजोबियम कल्चर नामक जीवाणु खाद से उपचारित कर अधिक उपज व नेत्रजन की बचत संभव है. राईजोबियम कल्चर एवं इसके प्रयोग करने की जानकारी विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है.

कीट वैज्ञानिक की सलाह :कीट वैज्ञानिक डॉ पीके सिंह ने दो ग्राम कारबेंडेजीम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार के बाद ही बोआई करने को कहा. उन्होंने मृदाजनित रोग व कीड़े से बचाव के लिए 5 एमएल क्लोरपाईरीफॉस प्रति किलो बीज की दर से उपचार करने की सलाह दी.।

हटिया स्थित मंडल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन

संवाददाता

रांची : 22 जुलाई 2020 को रांची रेल मंडल के हटिया स्थित मंडल अस्पताल में रिम्स रांची के संयुक्त सहभागिता से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

विशेष कर आज की परिस्थिति में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों, अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज एवं थैलेसीमिया से ग्रसित मरीजों के लिए खून की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया शिविर का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी सी हेंब्रम के मार्गदर्शन में किया गया। रक्तदान शिविर में 21 व्यक्तियों ने रक्तदान किया।

शिविर को सफल बनाने में रिम्स के डॉक्टर के के सिंह, डॉक्टर कविता देवघरिया, रांची रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधीक्षक ब्रजेश साहू, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, स्काउट के सुदीप मंडल ,तिलेश्वर कुमार साह ने सहयोग दिया।

फोटो न्यूज

बीएसएफ : सीमा की सुरक्षा के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा भी

बढ़ते वज़न के क्या-क्या कारण हो सकते है!

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

बढ़ा हुआ वज़न आजकल एक आम बात हो गई है और इससे जुड़ी समस्याएं भी । बढ़ता हुआ वज़न हमारे लुक्स को खराब करता तो है साथसाथ कुछ बिमारियों को भी नेवता देता है ,जैसे दिल का दौरा, किडनी पर असर होना इत्यादि। हम बात करेगें की बढ़ते हुए वज़न के क्या-क्या कारण है और इसे नियंत्रित कैसे कर सकते हैं।इस आर्टिकल को हम दो भागों में बाटते है पहले भाग में हम वज़न बढ़ने के कारण के बारे मे बात करेगें और दुसरे भाग में इसके उपाय के बारे मे बात करेगें।

वज़न बढने के कारण

■गलत खान-पान
गलत खाने पीने का मतलब है समय पर न खाना,दिन-भर खाते रहना भूख से ज्यादा खाना ,जंक फ़ूड खाना तली हुई चीजें ज्यादा खाना

■वंशानुगत हार्मोनस -कभी-कभी मोटापा वंशानुगत भी हो सकता है ऐसे में आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं।

■नींद पूरी न होना- नींद की कमी के कारण भी वज़न काफी बढ़ जाता है। देखा जाए तो अच्छी नींद न लेना और भी तकलीफो को नेवता देना है।

■बहुत मात्रा में दवाओं का इस्तेमाल करना- बहुत ज्यादा मात्रा मे दवाओं का सेवन या किसी एक दवाई से भी वज़न बढने लगता है। ऐसे में अपने डॉक्टर की सलाह ले।

■बढती उम्र- बढती उम्र में मेटाबौलिक रेट काफी कम हो जाता है जिसके कारण भी लोगों का वज़न काफी बढ जाता है।

■किसी खास बिमारी के कारण- कुछ ऐसी बिमारियों होती है जिससे वज़न काफी तेजी से बढ़ता है जैसे थाइरॉइड ।ऐसे में उचित उपचार करना जरूरी है।

■सूजन आना- कभी शरीर में सूजन आ जाता जिससे हम काफी मोटे दिखते हैं।

■धुम्रपान करना- अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने से भी वज़न बढने लगता है।

■शारीरिक गतिविधियों का कम होना- टेक्नोलॉजी के कारण लोग का काम काफी कम हो गया है और शारीरिक गतिविधियाँ कम हो गई है जिससे वज़न काफी तेजी से बढ़ता है।

ये तो वज़न बढने के कारण है अगले सप्ताह हम इसके उपाय के बारे मे बात करेगें।

हमसे जुडे.रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें ritusinghfitness.

बांस करील होता है औषधीय गुणों से भरा पूरा

सौरव कुमार मुंडा

हमारे दैनिक जीवन में बांस की उपयोगिता से हम सब भली भांति वाकिफ है। बांस का उपयोग बड़े पैमाने पर मकान बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही बांस से तरह-तरह के घरेलू सामान जैसे टोकरी सूप आदि भी बनाया जाता है। अब तो बांस से तरह-तरह के फर्नीचर और सजावट की चीजें भी बनाई जाने लगी है जोकि इको फ्रेंडली होने के साथ-साथ हैंडीक्राफ्ट को भी बढ़ावा दे रही है। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बहुत से क्षेत्रों में बांस की सब्जी को बड़े चाव से खाया जाता है। जी हां बांस की नन्हीं कोपलें जिन्हें करील कहा जाता है, खाने के उपयोग में लाया जाता है। करील की सब्जी, अचार, मुरब्बा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भी भरे पूरे होते हैं। आमतौर पर जून से अगस्त के माह में यह करील बांस की झुरमुट में आसानी से देखा जा सकता है। मानसून के आते ही हाट बाजारों में इसकी बिक्री होने लगती है। यूं तो बांस की घटती संख्या को देखकर करील की खरीद बिक्री या तस्करी पर कानूनन प्रतिबंध लगाया गया है फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी खरीद बिक्री खुलेआम होती है और अब तो इसकी मांग शहरों में भी अच्छी खासी होने लगी है।

आइए हम जानते हैं कि बांस करील में कौन-कौन से औषधीय गुण होते हैं:

- बांस की नन्हीं कोपलों में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कोपर, पोटेशियम, सल्फर, सेलेनियम और आयरन जैसे पोषक और खनिज तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें 19 तरह के एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं।
- बांस में फोलिक एसिड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसमें पाया जाने वाला फाइटोकेमिकल कैंसर से बचाव करता है तथा हृदय की धमनियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
- बांस के रस में अदरक का रस तथा शहद मिलाकर पीने से खांसी शांत हो जाती है।
- बांस की कोपलों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है, इसके सेवन से हड्डियाँ एवं दांत मजबूत होते हैं ।बांस से दातुन करने पर मुंह की दुर्गंध और दांत के दर्द दूर हो जाते हैं।
- करील से बनी सब्जी, मुरब्बे, और अचार के सेवन से वजन कम करने में मदद मिलती है, साथ ही कोलेस्ट्रोल भी घटता है और मधुमेह भी नियंत्रित होता है।
- पुरानी और मोटी बांस के गांठ में सफेद क्रिस्टल जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसे वंशलोचन के नाम से जाना जाता है, इसके सेवन से शरीर बलवान तथा हृदय मजबूत होता है।
- आयुर्वेद में वंशलोचन सितोपलादि चूर्ण बनाया जाता है जो पेट के अल्सर,खांसी-जुकाम, रक्त विकार, त्वचा की समस्या, अस्थमा, गठिया और बाल बढ़ाने तथा मजबूत करने में फायदेमंद होता है।
- बांस करील के सेवन से कफ़, सफेद दाग,सूजन आदि भी दूर होते हैं।

दोमुंहे सांप और सुनहरे उल्लू की कीमत पांच करोड़

एस टी एफ इकाई उज्जैन द्वारा एक दो मुंहा सांप (Sand boa) तथा एक सुनहरा उल्लू (Barn owl) के साथ आरोपियों को पकड़ा है। दो मुँहे सांप का सौदा 75 लाख रुपए में किया जा रहा था तथा सुनहरे उल्लू का सौदा एक करोड़ में किया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रत्येक की क़ीमत 3 से 5 करोड़ है

20 साल में समुद्र में मछलियों से ज्यादा होगी प्लास्टिक

- **अनुमान है कि 2040 तक समुद्र में मौजूद कुल प्लास्टिक वेस्ट बढ़कर करीब 60 करोड़ टन हो जाएगा।**
- **अनुमान है कि 2040 तक समुद्र में मौजूद प्लास्टिक वेस्ट में तीन गुना तक इजाफा हो जाएगा।**
- **2050 तक समुद्र में उतना प्लास्टिक होगा जितनी उसमें मछलियां भी नहीं हैं।**

यह जानकारी हाल ही में जारी एक नए शोध से सामने आई है। यह शोध द प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट और सिस्टेमिक नामक संस्था द्वारा किया गया है। इसमें एलेन मैकआर्थर फाउंडेशन, कॉमन सीस, ऑक्सफोर्ड और लीड्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सहयोग किया है। यह शोध अंतराष्ट्रीय जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ है।

शोध के अनुसार, 2016 में करीब 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में फेंका गया था। यदि दुनियाभर के देश और कंपनियां इसको रोकने में असफल रहती हैं तो यह 2040 तक बढ़कर 2.9 करोड़ टन हो जाएगा। यह दुनिया भर में समुद्र तट के प्रत्येक मीटर पर लगभग 50 किलोग्राम प्लास्टिक के बराबर होगा। चूंकि प्लास्टिक को खत्म होने में कई दशक लग जाते हैं, ऐसे में अनुमान है कि समुद्र में मौजूद कुल प्लास्टिक वेस्ट बढ़कर 60 करोड़ टन के करीब हो जाएगा। इसकी विशालता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह करीब 30 लाख ब्लू व्हेल मछलियों के वजन से भी ज्यादा होगा। इससे पहले ओसियन कन्ज़र्वेंसी नामक संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, हर साल करीब 80 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में फेंका जा रहा है। अनुमान था कि करीब 15 करोड़ टन कचरा समुद्रों में मौजूद है। यह पर्यावरण और समुद्री इकोसिस्टम को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है।

एक नजर लोहरदगा के लावापानी जलप्रपात की ओर

आकाश साहू

लोहरदगा जिला जिसको बॉक्साइट नगरी भी कहा जाता हैं। मुख्यालय से 26 की. मी. दूर पेसरार प्रखंड में स्थित एक बहुत ही सुंदर मनमोहक जलप्रपात है, जिसे लावापानी जलप्रपात कहा जाता हैं। यह जलप्रपात नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार में होने के करण से उतना प्रशिध्द ना हो सका फिर भी लोहरदगा जिले में नक्सल गतिविधि में कमी होने से यह जलप्रपात का विकास जिले में हुआ। पेशरार प्रखंड लोहरदगा का एक ऐसा प्रखंड रहा है, जिसमें माओवादी का राज शुरु से रहा है, यह प्रखंड गुमला और लातेहार जिला के सीमाओं को भी छूती है, जिससे लातेहार जिले के खुख्यात इनामी नक्सली भी इस क्षेत्र में फलते-फूलते थे। जिला मुख्यालय से सुगम रास्ता नहीं होने से यह प्रखंड बहुत ही पिछड़ा था। सड़क निर्माण में आगजनी, लेवी मांगना या मुधभेड़, किसी को जान से मारना इस क्षेत्र में आम थीं। इस क्षेत्र की प्राकृति क सुन्दरता भी इस नक्सली गतिविधि के कारण छुपी हूई थी। वर्ष 2014 से पहले इस क्षेत्र में कोइ जाना नहीं चाहता था। शायद इसके पीछे नक्सली संगठनों का दबदबा या उनका डर था।

वर्ष 2014 में से इस क्षेत्र के लोगों में विकास की आस जगी और वह पूरी भी हूई। इस क्षेत्र के विकास की चर्चा यहां के एसपी रहे कार्तिक सर के बगैरअधूरी रहेगी। एस० पी० कार्तिक के इस क्षेत्र और लावापानी की विकास में काफ़ी योगदान रहा है,इनके कार्यकाल में घाटियों में सड़क निर्माण से लेकर नक्सल गतिविधियों में कमी आयी। इनके कार्यकाल में ही लावापनी को पर्यटक स्थल बनाने में काफ़ी सारहनीय कार्य हुये ।

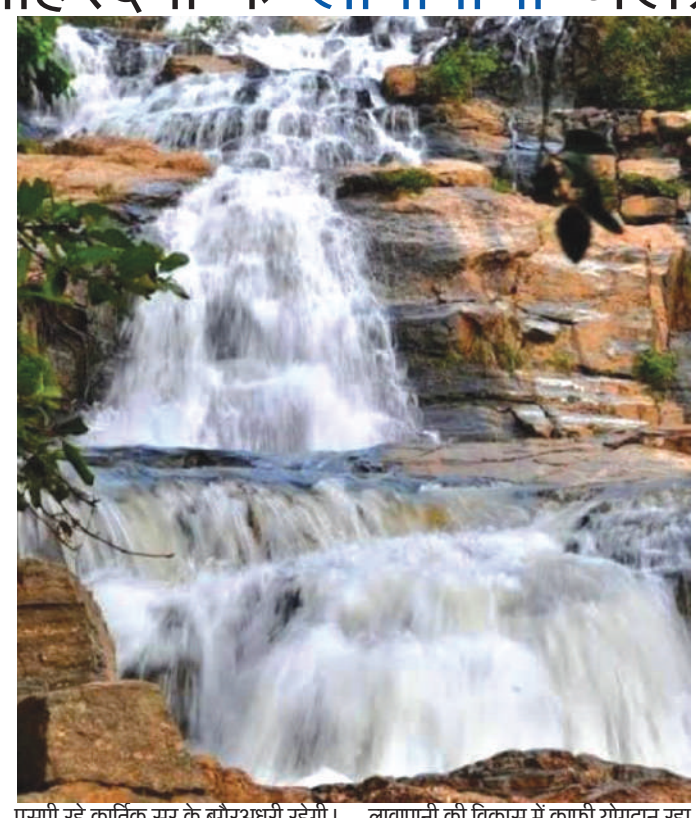

पेशरार घाटी से जिला मुख्यालय तक वर्ष 2016 में पक्की सड़क पूरी तरह बन गया साथ ही वर्ष 2018 तक इस छेत्र के गांव तक बिजली भी पहुंच गया और नक्सली गतिविधि भी अब कम हो गई हैं। जिस कारण लावापानी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो पाया। लावापानी पहाड़ों के बीच बहुत मनोरम दृश्य खुद में छुपा के बैठा है, चाहे पेशरार की घाटी हो या रास्ते में एक छोटा सा केकरांग जलप्रपात। लोहरदगा से शुरू हुई यह यात्रा रोमांच से भरपूर है। आज भी यह क्षेत्र और लावापानी खुद में समृद्धि होने के बाद भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है, यहां के लोग इसे राज्य के मशहूर पर्यटक स्थल के रूप में देखना चाहते है। और इसकी सुन्दरता को अगर देखा जाय तो यह जलप्रपात खुद में मनोरम दृश्यों को समाऐ बैठा है।

अगर आप को भी पहाड़ों, घाटियां, नदियां, जंगल और झरना जैसी प्रकृति से प्रेम है घूमने का शौक रखते है तो एक बार लोहरदगा जिले का यह जलप्रपात का सैर कीजिए यह आपको कभी निराश नहीं करेगा।

बीएयू में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने पर जोर

अजय कुमार

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में कार्यरत गृह विज्ञान विभाग में कृषि उत्पादों जैसे रागी (मडुआ), सोयाबीन, सब्जियों एवं फलों का वैज्ञानिक तकनीकों से प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन द्वारा विभिन्न उत्पादों का उत्पादन तथा प्रशिक्षण चलाये जाते है. आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण के साथ -साथ महिला सशक्तिकरण के लिए गृह वाटिका आदि विषयों में अनेकों कार्यक्रम चलाये जाते है.

शुक्रवार एवं शनिवार को विभाग के कार्यो की समीक्षा डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने की. उन्होंने कृषि कार्य को लाभकारी बनाने तथा किसानों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उपेक्षित फसलों व अतिपोषित अनाजों जैसे - बाजरा, ज्वार, जौ, कसावा, राजमा, बोदी, ओल, अदरख, जिमीकंद एवं शकरकंद आदि के प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन तकनीक को विकसित करने का परामर्श दिया. उन्होंने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं खाद्य सुरक्षा के नये आयामों को जोड़ने तथा बाजार व्यवस्था के अनुरूप व्यावसायिक उत्पादन के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया.

विभागाध्यक्ष डॉ रेखा सिन्हा ने बताया कि यूजीसी से मान्यताप्राप्त 'बैचलर ऑफ़ वोकेशनल इन ह्यूमन न्यूट्रीशन एंड डाईटेटिकस' विषय पर वर्ष 2018-19 से तीन वर्षीय कोर्स भी चलाया जा रहा है. इसमें सीटो की संख्या 50 और न्यूनतम योग्यता

10 + 2 पास है. कोर्स के बाद छात्र देश के किसी भी संस्थानों में ह्यूमन न्यूट्रीशन तथा डाईटेटिकस पर उच्चतर शिक्षा में नामांकन ले सकते है. पंजीकरण कराकर डाइटीसीयन का प्रैक्टिस कर सकते है.

साथ ही कृषि संकाय में अध्ययनरत कृषि स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों ने 6 महीने के अनिवार्य अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम के तहत प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन पर कार्यानुभव एवं प्रायोगिक ज्ञान से उद्यमिता के गुर से प्रशिक्षित किया जाता है. इस वर्ष छात्रों को गेहूँ, मडुआ (रागी), मकई, सोयाबीन, बाजरा, चना, ज्वार एवं चौलाई (एमेरैनथश) के दानों के उपयोग से मल्टीग्रेन आटा बनाने तथा गेहूँ, मडुआ (रागी), सोयाबीन, जौ, बाजरा, जई तथा फेनु ग्रीक के दाने के उपयोग से डायबेटिक फ्रेंडली आटा को बनाना सीखा, मल्टीग्रेन आटा व डायबेटिक फ्रेंडली आटा की बिक्री की तथा बैंक के लिए डीपीआर बनाया.

वर्तमान में प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन के नवीनतम तकनीकों से रागी (मडुआ) से बिस्कुट, केक, सेवई तथा सोयाबीन से टोफू (पनीर) का उत्पाद तैयार किया जाता है. साथ ही मशरूम के आचार, टोमेटो कैचप, सब्जियों के आचार तथा फलों के जेम व जेली उत्पाद का निर्माण कार्य के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है।

E ZONE CARE

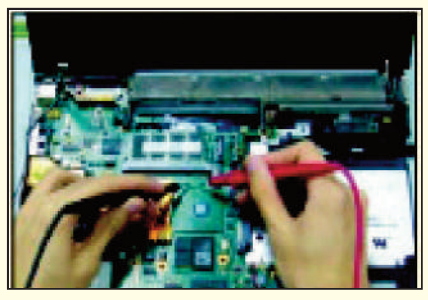

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।